

अस्पताल ले जाते हुए ही वह करीबन मृत हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु का मुख्य कारण पसलियों का टूटना और हृदय आघात (हार्ट अटैक) था। इस घटना के दौरान सैकड़ों लोग, जिसमें हमारे सम्भ्रात घरों से आने वाले छात्र, प्रशासन के अधिकारी और बहुत से प्रोफेसर उपस्थित थे, लेकिन उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई।

चूँकि मामला एक कॉलेज के प्रोफेसर का था, इसलिए मामला न्यायालय तक पहुँचा (जहाँ 12 जुलाई, 2009 को नागपुर की एक सेशन कोर्ट द्वारा ए.बी. वी.पी. के 6 कार्यकर्ताओं को जो कि मुख्य अभियुक्त थे बाइन्जुत बरी कर दिया गया। निर्णय सुनाते वक्त न्यायधीश श्री नितिन दाल्वी ने कहा कि प्रो. सम्भरवाल के साथ न्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोगी पक्ष, यह साबित नहीं कर सका कि ए.बी.वी.पी. के वे 6 कार्यकर्ता उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। पूरे ट्रायल के दौरान करीब 69 लोगों को तलब किया गया, परन्तु उसमें से कोई भी अपराधियों को पहचान नहीं सका। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मध्यप्रदेश सरकार उसके मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका रही, यह जगजाहिर है। उन्होंने शुरू से ही कहा था, कि प्रो. सम्भरवाल की मृत्यु एक आम घटना थी जिसमें ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ताओं का कोई लेना-देना नहीं था। शुरू से ही उन्होंने अभियुक्तों को संरक्षण देने के अलावा माधव कॉलेज के चपरासी से लेकर प्रोफेसर तक सबकी भूमिका तय करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। पूरे घटनाक्रम के साथ 'न्याय' हो, इसके लिए उन्होंने पूरे मसले की स्वयं ही देखरेख की और खुले तौर पर इसे स्वीकार भी किया। उन्होंने शुरू से ही यह बयान दिया कि प्रो. सम्भरवाल की मृत्यु एक आम घटना थी, जिससे ए. बी.वी.पी. के कार्यकर्ताओं का कोई लेना-देना नहीं है। निर्णय आने के बाद भी उन्होंने 'न्याय की विजय' का उद्घोष किया। वैसे शिवराज सिंह चौहान जैसे फ़ासिस्ट से यही उम्मीद थी, जिस पर

पूरा मीडिया और शहरी मध्यवर्ग इस तरह हो-हल्ला मचा रहा है, मानो यह पहली बार हुआ हो। जगदीश टाइलर, नरेन्द्र मोदी, योगी आदित्यनाथ आदि जब कानूनी संरक्षण के साथ छुट्टा घूम सकते हैं तो भला ए.बी.वी.पी. के यह 6 गुण्डे क्यों नहीं।

सवाल यह है कि क्या इन सभी घटनाओं के केन्द्र में महज न्यायपालिका

की असफलता है, या तलब किये गये गवाहों की दुनियादारी या कुछ और। अगर हाँ तो उन लाखों घटनाओं का क्या जिसमें बलात्कार से लेकर जला कर मार देने वाली घटनाओं के केस जो न्यायालय की दहलीज और मीडिया के कानों तक पहुँच भी नहीं पाते!

— शिवार्थ पाण्डेय

जपो स्वदेशी-जपो स्वदेशी, पूँजी लाओ रोज़ विदेशी

स्वदेशी का राग अलापने वाला संघ परिवार (आर.एस.एस.) अपने राजनीतिक मसूबों के लिए यह विदेशी चन्दे का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकती। इसी कड़ी में संघ परिवार की विभिन्न शाखाओं को विदेशी चन्दा मिलने की बात सामने आई। फण्ड जुटाने का काम यह तथाकथित "देशभक्त" काफ़ी लम्बे समय से गौरवशाली हिन्दू अतीत के खतरे के नाम पर करते रहे हैं। इसी कड़ी में 9 अगस्त 2009 के नई दुनिया अख़बार के पहले पन्ने पर छपी खबर से यह सच्चाई एक बार फिर सामने आई। सीबीआई जाँच के दौरान पाया गया कि संघ परिवार के विभिन्न संगठन को विवेकानन्द के नाम पर, शिक्षा के नाम पर (भगवाकरण के लिए), राम के नाम पर, आदिवासियों के कल्याण के नाम पर, आपदा के नाम पर करोड़ों रुपये का विदेशी चन्दा मिला है। मसलन, 2006-07 में विदेशी चन्दा पाने वाले संगठनों में विवेकानन्द रॉय मेमोरियल केन्द्र (तमिलनाडू) को 54 लाख 53 हजार 346 रुपये मिले। उतर प्रदेश में सक्रिय शिक्षा भारती संस्था को 27 लाख 56 हजार 400 रुपये मिले तो इसी राज्य में सक्रिय श्री राम विकास समिति को 22 लाख 11 हजार 870, उत्तराखण्ड में दैवी आपदा पीडित सहायता समिति को 17 लाख 90 हजार 800, झारखण्ड में बनवासी कल्याण केन्द्र को 6 लाख 50 हजार 430 और केरल में सक्रिय

वनवासी आश्रम ट्रस्ट को 5 लाख 59 हजार 876 रुपये मिले।

विदेशी चन्दे की बात तो एक तरफ़ संघ परिवार का विचार और आचार से भी स्वदेशी नहीं है। और न ही गणवेश (यूनीफ़ार्म) और नाम से स्वदेशी। नाम के सन्दर्भ में खुद आर.एस.एस. के सर्वोच्च नेतृत्व ने हिटलर की नाज़ी पार्टी (नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का संक्षिप्त रूप) और इटली की फ़ासीवादी पार्टी (इतालवी भाषा में 'फ़ासी' शब्द संघ का पर्यायवाची होता है) की प्रेरणा को अपने लेखन में स्वीकारा था और यहाँ तक कि संघ के स्वयंसेवकों का गणवेश (यूनीफ़ार्म) भी स्पेनी और इतालवी फ़ासिस्टों से प्रेरित है। दुनिया में अगर इटली के फ़ासिस्टों की पहचान 'काली कमीज़' और स्पेन के फ़ासिस्टों की पहचान 'भूरी कमीज़' वालों के रूप में थी तो संघियों ने अपनी पहचान 'खाकी निकर' और 'काली टोपी' वालों के रूप में कायम की। अगर वैचारिक सन्दर्भ में बात करें तो डा. केशवराव बलीराम हेडगेवार के सहयोगी डॉ. मुंजे ने इटली के नेता मुसोलिनी से मुलाकात तक की थी। और वैचारिक प्रसाद लेकर स्वदेश लौटे थे। संघ परिवार का सांगठनिक ढाँचा और कार्यप्रणाली भी कुछ हिटलर की नाज़ी पार्टी और मुसोलिनी की फ़ासीवादी पार्टी से अद्भुत ढंग से मेल खाता है न कि भारतीय संस्कृति के किसी अध्याय से। इसका सांगठनिक ढाँचा न तो किसी तरीक़े के संविधान को मानता

है और न ही अपने पदाधिकारियों के चुने जाने के अधिकार को। चाहे नये सदस्य के भर्ती के वक्त संघ के सरसंघ चालक के प्रति पूर्ण और प्रश्नहीन निष्ठा की सदस्यता की शर्त का सवाल हो या जनवाद का। सांगठनिक ढाँचा चालकानुवर्ती (कमाण्ड स्ट्रक्चर) होता है। संघ की कार्यप्रणाली भी हिटलर-मुसोलिनी की तरह रैलियों के समय मंच के सामने सबसे पहले आर. एस.एस. के वर्दीधारी स्वयंसेवक बैठते हैं और संघ के नेता को हिन्दुओं के वीर सेनानी की तरह प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि इनका राष्ट्रवाद भी हिटलर के वृहत्तर जर्मनराष्ट्र जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा, बवारिया तथा चेकोस्लोवाकिया को मिलाकर बनाया गया था की तर्ज पर है। उसी तरह 'अखण्ड भारत' की बात भी पाकिस्तान, भारत, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल आदि को मिलाकर की गई है। हेडगेवार से गोलवलकर तथा अशोक सिंघल, प्रवीण तोगडिया, नरेन्द्र मोदी के भाषणों की शैली की बात हो या गुजरात में मुसलमानों का सफ़ाया अभियान हो या कश्माल में ईसाईयों का - यह भी जर्मनी के यहूदियों के सफ़ाये अभियान की तर्ज पर किया गया है। संघ परिवार का 'राष्ट्रवाद', मुसलमानों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा और हिन्दू जाति के प्रति श्रेष्ठताबोध की बात करता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ समूचे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के दौरान आर.एस.एस. ने कभी हिस्सा नहीं लिया। संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी चमड़ी बचाने के लिए आजादी के सिपाहियों के खिलाफ गवाही देने तक के प्रमाण उपलब्ध हैं।

संघ परिवार के 'स्वदेशी' आर्थिक चिन्तन और राजनीतिक अवधारणाओं तक की असलियत भी जानना जरूरी है। संघ शुरू से अमेरिकी किस्म के पूँजीवादी मॉडल और अमेरिकापरस्त विदेशनीति का समर्थक रहा है। जिसको अपने भोपू 'ऑर्गनाइज़र' में भी स्वीकारा है। इसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी खुले बाज़ार की नीतियों और विदेशी पूँजी की मदद से देश के आर्थिक विकास की हिमायती रही है। अपने कार्यकाल में

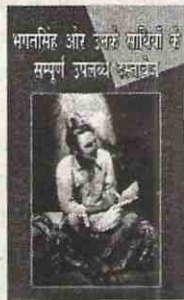
सरकार ने खुद जनता की गाढ़ी कमाई से खड़े किये सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अरुण शोरी के नेतृत्व में बाकायदा एक विनिवेश मन्त्रालय खोला गया था।

संघ का अगर चाल-चेहरा और चरित्र सबकुछ हिटलर-मुसोलिनी की तरह विदेशी है यहाँ तक की आत्मा भी, तो यह विदेशी चन्दे को इस्तेमाल करने से क्यों चूके। संघ परिवार भारतीयों से भी चन्दा इस्तेमाल करने में नहीं चूकती। पिछले वर्ष ही दो उद्योगपतियों के नाम सामने आये थे। जब संघ परिवार की शाखाओं में शामिल होने वाले लोगों की गिनती में कमी 60 हजार से 20 हजार के करीब रह गयी थी। इस स्थिति से उबरने के लिए आर.एस.एस. ने उद्योगपतियों के आगे मदद की अपील की थी और एक हिन्दू फण्ड बनाने की योजना बनाई थी। संघ ने इस फण्ड का प्रयोग एक तरफ़ दिल्ली और प्रदेश की राजधानियों में उच्च पदों पर विराजमान नौकरशाहों और सेना के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध स्थापित करके उनके बीच संघ की विचारधारा ले जायेंगे और कॉरपोरेट जगत के युवाओं को अपने रंग में रँगने की कोशिश के लिए।

यह कोई पहली और अन्तिम पोल नहीं होगी जो खुलेगी एक और तथ्य से इस बात से भी अन्दाज़ा लगाया जा सकता

है कि 15वीं लोकसभा में संघ परिवार की राजनीतिक शाखा भाजपा (नीत राजग गठबंधन फ़िलहाल विपक्ष की भूमिका में है) ने 129 करोड़पतियों को टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा ने भी साढ़े 52 करोड़ रुपये पूँजीपतियों से लिए। भाजपा में भी अन्य पार्टियों की तरह संसद में धनपतियों की सीधी भागीदारी बढ़ी है। स्वयं चुनाव आयोग के अधिकारी वाई. एम. कुरेशी ने माना है कि चुनाव आयोग चुनावों में काले धन के उपयोग को रोकने में असफल रहा है। संघ अपने दर्जनों अन्य संगठनों - ए.बी.वी.पी., विहिप, बजरंग दल, श्रीराम सेना आदि भारत में फ़ासीवादी नीतियों को लागू करने का प्रयास कर रहा है। चाहे इस वक्त वह सत्ता में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। संघ के अलावा अन्य ऐसे संगठन देश में जनता को जाति, धर्म, गोत्र, नस्ल, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, अस्मिता, राष्ट्र आदि के नाम पर हमारे बीच नफ़रत के बीच बोते रहेंगे जब तक इसका मानवद्रोही, गैरजनतान्त्रिक, पुरातनपन्थी ताक़तों का जनता के बीच परदाफ़ाश नहीं कर देते और एक बेहतर विकल्प नहीं रखते, तब तक फ़ासीवाद का यह दानव मेहनतकश समाज को निगलता जायेगा। क्रान्तिकारी ताक़तें ही सचेतन रूप से इनको जनता की ताक़त के बल पर दफ़ना सकती हैं।

- शाम



भगतसिंह और उनके साथियों के सम्पूर्ण उपलब्ध दस्तावेज़

भगतसिंह का चिन्तन परम्परा और परिवर्तन के द्वन्द्व का जीवन्त रूप है और आज, जब नयी क्रान्तिकारी शक्तियों को एक बार फिर संगठित होकर साम्राज्यवाद और देशी पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष की दिशा और मार्ग का सन्धान करना है, जब एक बार फिर नयी समाजवादी क्रान्ति की रणनीति और आम रणकौशल विकसित करने का कार्यभार हमारे सामने है तो

भगतसिंह की विचार-प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों से हमें बहुमूल्य चीज़ें सीखने को मिलेंगी।

भगतसिंह और उनके क्रान्तिकारी साथियों के समस्त उपलब्ध दस्तावेज़ों का पहला सम्पूर्ण संकलन। (पृ. 752, मूल्य: रु. 200)

प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:

जनचेतना, डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226020